3 स्मृति शेषः प्रोफेसर प्रेम बिहारी यदु

5 अद्भुत लीडरशिप योग्य राजनेता है प्रियंका गांधी

8 उमंग सिंघार का हुआ भव्य स्वागत

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 41 प्रति सोमवार, 17 फरवरी 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश और विदेश के मेहमानों के स्वागत में 1500 करोड़ लुटायेगी मोहन सरकार

मोहन यादव ने प्रदेश के करोड़ों रुपये किए बर्बाद, निवेश के नाम पर होती है सिर्फ बैठकें, हो रहा है विदेश में परिवार सहित सैर सपाटा

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं। तैयारियां जोरों पर होने का का एक सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का समिट में शामिल होना। इसके साथ ही देश विदेश से भी कई निवेशक भोपाल आ रहे हैं। इस समिट के लिए मोहन सरकार पानी के तरह पैसा बहा रही है। बताया जा रहा है कि इस दो दिनों के आयोजन में लगभग

1500 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में मोहन यादव इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर अरबों रुपये बर्बाद किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने आपको स्थापित करने के चक्कर में प्रदेश की खस्ता हालत को और खस्ता करने पर तुले हैं। इससे पहले भी प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट हुई हैं। मोहन सरकार में ही कोई सात समिट हो चुकी हैं। यह आठवीं समिट है। अब इन सात समिट की बात की जाये तो अभी तक कोई भी उदयोग जमीन पर नहीं उतरा है। लेकिन आज सवाल फिर वही उठ रहा है कि आखिर जब समिट का आउटपुट नहीं निकल रहा है तो समिट करने का क्या मतलब। इन समिट में भी प्रदेश सरकार का अरबों रूपये खर्च होता है। पूरा प्रशासन कई दिन पहले से तैयारियां करता है।

आज मोहन यादव के कार्यों का अवलोकन करें तो एक तरफ वो इन्वेस्टर्स समिट कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के युवा उद्यमी अपना स्टार्ट-अप को प्रदेश में बंद कर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर दूसरे प्रदेश चले गए हैं। जैसे कि युवा उद्यमी प्रतीक और दीपेश ने अपनी स्टार्ट-अप वंडर लूम्स को मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने के कारण प्रदेश छोड़ना पड़ा। वहीं यह स्टार्ट-अप अब पुणे में बहुत अच्छा कर रही है।

(शेष पेज 6 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव की कर्मठता और सक्रियता से खुले किसानों और कृषि के लिये समृद्धि के द्वार

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी सरकार ने प्रदेश के किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने और उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बेटियों सहित समाज के समग्र कल्याण के लिये समर्पित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। इसके अंतर्गत सरकार ने किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी तथा दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान करके एक ओर जहां अपना संकल्प पूरा किया है। वहीं दूसरी ओर किसानों से बीते खरीफ विपणन वर्ष में 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर एक नया रिकार्ड कायम किया है। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 32 हजार करोड़ रूपए का भुगतान एवं किसान समृद्धि योजना के माध्यम से मूल्य की अंतर की राशि 13,320 करोड़ का भुगतान करके यह बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का रास्ता खेती-किसानी से ही निकलेगा। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़; भाजपा ने 10 नगर निगमों में से सभी 10 पर कब्जा जमाया

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत की वजह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं जिन्होंने प्रदेश के हर जिले में जनता के बीच ये बात स्थापित करने का प्रयास किया कि काम हो रहा है। 14 महीने की भाजपा सरकार ने 7400 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। इसका असर हुआ।

6 से अधिक दशकों तक देश पर राज करने वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का भविष्य संकट में

मध्यप्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व बचाये रखने में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की हो सकती है बड़ी भूमिका

-विजया पाठक

देश की आजादी के बाद से लगभग 06 दशक तक भारत पर शासन करने वाली प्रमुख राजनैतिक पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का भविष्य आज संकट में नजर आ रहा है। पिछले एक दशक में नजर डालें तो पार्टी ने न सिर्फ अपने प्रमुख और दिग्गज नेताओं को खोया है, बल्कि देश के प्रमुख राज्यों से उसे सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा है। आज स्थिति यह बन गई है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार देश के इक्का-दुक्का राज्यों में है। वह भी उन राज्यों में है जिनका योगदान केन्द्र सरकार बनाने में नाम मात्र होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यही दशा और दिशा रही तो आगामी समय में कांग्रेस का क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा की साजिश का शिकार होते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी पहचान खो दे। उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जिस दिल्ली में लंबे समय तक शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने शासन किया आज उसी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ में एक भी सीटें नहीं लग पाई। (शेष पेज 2 पर)

मध्यप्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व बचाये रखने में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की हो सकती है बड़ी भूमिका

पार्टी आलाकमान को पहल कर मध्यप्रदेश में बड़े फेरबदल करने पर करना होगा विचार

(पेज 1 से जारी)

यानि कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई है। यह कांग्रेस और उसके पार्टी शीर्षस्थ के लिये बड़ा चिंता का विषय है कि दिल्ली जैसे राज्य में अगर पार्टी की एक सभी सीट न आये तो भला देश की जनता उनसे क्या अपेक्षा करे।

लगभग अप्रांसिगक हो गया है विपक्ष

राजनैतिक विश्लेषकों की मानें तो कांग्रेस पार्टी अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है और अब उसे लगातार अभूतपूर्व चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है। एक समय अजेय रही और स्वतंत्र भारत पर करीब पांच दशकों तक शासन करने वाली राजनीतिक दिग्गज कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी को आम चुनावों में भारी जीत हासिल करने से रोकने में विफल रही। यहां तक कि स्थानीय क्षेत्रों में मजबूत पकड़ का दावा करने वाली क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियों को भी अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, जिससे कम से कम अभी के लिए विपक्ष लगभग अप्रासंगिक हो गया है।

मध्यप्रदेश में कमलनाथ ने किया था एकजुट

वहीं, अगर मध्यप्रदेश की बात करें तो वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्व

विजय:)

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जबरदस्त नेतृत्व करते हुए चुनावी मैदान में फतह प्राप्त की। लेकिन सिंधिया जैसे नेता की वजह से कमलनाथ को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन कमलनाथ की कर्मठता और सक्रियता फिर भी कम नहीं हुई और वे लगातार राज्य में सक्रिय रहे और उन्होंने वर्ष 2023 के चुनाव में पूरी सक्रियता के साथ करते हुए पार्टी को भाजपा के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जब कांग्रेस अंतर्कलह के कारण चुनाव हारी तो शीर्षस्थ ने कमलनाथ पर भरोसा न करके बड़ा धोखा पाया जिसका परिणाम है कि अभी तक प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए उसमें न तो कांग्रेस जीत प्राप्त हुई और न ही कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में सही ढंग से सक्रिय हो पा रही।

कमजोर विपक्ष के कारण भाजपाई हावी

वहीं, अगर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालें तो इसमें कोई दो मत नहीं कि वर्तमान कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप बेहद कमजोर है। यही कारण है कि विधानसभा हो या फिर सरकार को घेरने की बात विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस हर बार पीछे रही। यही नहीं विपक्षी दल के होने के नाते पार्टी ने ऐसे कई प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरना तक उचित नहीं समझा जिनसे मोहन यादव की सरकार को झटका पहुंच सकता था। फिर बात चाहे नर्सिंग घोटाले की हो, या फिर आरटीओ पुलिस आरक्षक सौरभ शर्मा के पास प्राप्त हुई बेनामी संपत्ति का। महिलाओं से लेकर युवाओं के बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है लेकिन विपक्षी नेता पूरी तरह से उदासीन हैं और हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान को अगर भविष्य मप्र में कांग्रेस का बचाकर रखना है तो एक बार फिर नये सिरे से इस दिशा में प्रयास करना होगा, वरना भगवान भरोसे चल रही कांग्रेस का अस्तित्व आगामी विधानसभा चुनाव तक पूरी तरह से समाप्त होता दिख रहा है।

फिर से जताना होगा पुराने नेताओं पर भरोसा

कांग्रेस पार्टी आलाकमान को वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक बार पुनः मंथन करने की आवश्यकता है। पार्टी शीर्ष दल को अपने पुराने नेताओं पर एक बार फिर भरोसा दिखने की आवश्यकता है। चाहे बात मध्यप्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की हो या फिर राजस्थान में अशोक गहलोत की। पार्टी को इन सभी पुराने नेताओं को एक मंच पर लाकर एकजुट करना होगा और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में और दम तथा भरोसे के साथ मैदान पर उतरना होगा तभी पार्टी राज्यों और केंद्र में सरकार लाने में सफल होगी।

लोकसभा चुनाव में उम्मीद जगी लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा

जब मार्च में आम चुनाव की घोषणा की गई, तो उम्मीद की किरण जगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकती है और उसे अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ सरकार बनाने का एक छोटा सा मौका मिलेगा। यह संभावना 2018 के अंत में हुए राज्य चुनावों में पार्टी की चुनावी सफलताओं के कारण उभरी, जिसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी ने सरकारें बनाईं। मोदी को चुनौती देने के लिए एकजुट विपक्ष बनाने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रीय विपक्षी दलों द्वारा कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के परिदृश्य के साथ यह संभावना तेज हो गई। लेकिन मतदान का समय नजदीक आने के साथ ही नेतृत्व स्तर पर मतभेदों के कारण विपक्ष बंटा हुआ होने के कारण यह संभावना जल्द ही खत्म हो गई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव की कर्मठता और सक्रियता से खुले किसानों और कृषि के लिये समृद्धि के द्वार

(पेज 1 से जारी)

छत्तीसगढ़, देश में प्रथम स्थान पर रहा है

देश में यह गौरव की बात है कि सेंट्रल पूल में धान के योगदानकर्ता राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने वाला तथा धान का सर्वाधिक 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से मूल्य देने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक 24.75 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदने वाला छत्तीसगढ़, देश में प्रथम स्थान पर रहा है। विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की गई। चालू खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है।

जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान

देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और यह धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने एक साल की अवधि में राज्य के किसानों के हित में लिए गए फैसलों से खेती-किसानी को नया सम्बल मिला है। किसानों का मानना है कि राज्य सरकार के फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार किसानों की हितैषी है। खेती-किसानी ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल कृषि के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 03 हजार 435 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान

छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन कृषि ऋण 01 अप्रैल 2014 से उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण की अधिकतम सीमा 05 लाख रूपए तक है। फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 60 अनुपात 40 है। सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए खरीफ वर्ष 2024 में 15.21 लाख किसानों को 6912 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वितरित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

समन्वित प्रयास पर राज्य सरकार का फोकस

छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सौर सुजला योजना के माध्यम से सिंचित रकबे में बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जा रहा है। नवीन सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रूपए, लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं के लिए 692 करोड़ रूपए, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ रूपए एवं एनीकट तथा स्टाप डेम निर्माण के लिए 262 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार, कृषि एवं सहायक गतिविधियां के लिए समन्वित प्रयास पर राज्य सरकार का फोकस है।

तिलहन में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई

छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 48.08 लाख हेक्टेयर तथा रबी फसलों का क्षेत्र 18.06 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न सिंचाई स्रोतों से खरीफ मौसम में 16.04 लाख हेक्टेयर के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जो निरा फसली क्षेत्र का 35 प्रतिशत है। राज्य में कुल 40.11 लाख कृषक परिवार है जिसमें से 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं। प्रदेश में 33 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति के कृषक परिवार हैं। खरीफ उत्पादन में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में कुल अनाज में 03 प्रतिशत, दलहन में 09 प्रतिशत एवं तिलहन में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उत्पादकता में 8वें स्थान पर

भारत सरकार द्वारा जारी कृषि सांख्यिकी सारणी वर्ष 2022 के अनुसार धान फसल के क्षेत्राच्छादन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में चौथे, धान फसल के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में 7वें तथा धान फसल के प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में छत्तीसगढ़ राज्य देश में 11वें स्थान पर है। खाद्यान्न फसलों के क्षेत्राच्छादन में छत्तीसगढ़ देश में 10वें, उत्पादन में 15वें तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में 16वें स्थान पर हैं। चना फसल क्षेत्राच्छादन में छत्तीसगढ़ देश में 8वें, कुल उत्पादन में 9वें तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में 8वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन होने से अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी-बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे, इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा।

नक्सलियों से निर्णायक लड़ाई में आगे बढ़ता छत्तीसगढ़

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। हाल ही में छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ा ऑपरेशन बीजापुर में हुआ। जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में पुलिस व नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। पुलिस सुरक्षा बल ने छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर 31 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं दो जवान बलिदान और दो जवान घायल भी हुए हैं। जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है। आज छत्तीसगढ़ न केवल शांति की ओर बढ़ रहा है, बल्कि विकास के नए आयाम भी स्थापित कर रहा है। साय सरकार में प्रदेश ने नक्सल उन्मूलन के प्रयासों में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई प्रभावी नीतियों और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण ने राज्य में स्थायी शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में बीते 13 महीनों में 305 नक्सली मारे जा चुके हैं, 1177 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 985 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह आंकड़े न केवल सरकार की प्रतिबद्धता और कुशल रणनीति को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी प्रमाणित करते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सल हिंसा से मुक्त होकर शांति और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ को न केवल नक्सल मुक्त बनाना चाहती है, बल्कि इसे शांति और विकास का प्रतीक राज्य भी बनाना चाहती है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को नक्सल हिंसा से मुक्त कर स्थायी शांति और समृद्धि की ओर ले जाने का सशक्त विश्वास का माहौल बना रही है।

लगातार हो रहे बड़े ऑपरेशन

सिर्फ इन्द्रावती नेशनल पार्क ही नहीं इससे पहले 02 फरवरी को कोरचोली में हुए एक ऑपरेशन 08 नक्सली मारे गए थे। 20 जनवरी, 2025 को ही गरियाबंद में भी पुलिस एनकाउंटर हो चुका है। इस एनकाउंटर में 29 नक्सली मारे गए थे। 16 जनवरी

पिछले एक साल 305 नक्सली हुए ढेर

प्रमाण है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सल समस्या केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और विकासात्मक चुनौती भी है। उनकी सरकार ने इस समस्या को एक समग्र दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें उन्हें रोजगार, आर्थिक सहायता और समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह पुनर्वास नीतियां न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं, बल्कि समाज में भी शांति और को हुए ऑपरेशन में सुकमा में 18 नक्सली मारे गए थे। इससे पहले अबूझमाड़ में 05 नक्सली मार गिराए गए थे। यह एनकाउंटर छतीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अलग-अलग इलाकों में हुए हैं। इनमें अबूझमाड़ और गरियाबंद आदि नक्सलियों के गढ़ रहे हैं। अब इन इलाकों में सुरक्षाबलों के सैकड़ों कैम्प हैं।

आत्मसमर्पण पर भी जोर

सुरक्षाबल लगातार नक्सलियों के बड़े गुट साफ़ कर रहे हैं। आँकड़ों के अनुसार, 2024 में ही छत्तीसगढ़ के भीतर 239 नक्सली मार गिराए गए थे। 2025 में छत्तीसगढ़ में 87 नक्सली मार गिराए जा चुके हैं। सुरक्षाबल नक्सलियों को मार ही नहीं रहे बल्कि उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 में छत्तीसगढ़ के भीतर 925 नक्सली गिरफ्तार भी किए गए थे। इसके अलावा 738 ने नक्सलवाद की राह छोड़कर आत्म समर्पण किया था। छतीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि नक्सलियों के बहकावे में आए लोग वापस मुख्यधारा में जुड़ जाएँ। हालाँकि, सुरक्षाबलों को लगातार निशाना बनाने वाले नक्सली मान नहीं रहे। ऐसे में उसने उनका सफाया करने का निर्णय कर रखा है।

हिंसा में तेजी से आई कमी

नक्सली हिंसा में बीते कुछ वर्षों में तेजी से कमी आई है और उन इलाकों में विकास भी हुआ है। लोकसभा में गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए एक जवाब के अनुसार, 2010 में देश में 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे लेकिन यह संख्या 2024 में घटकर 90 आ गई। 2010 में देश में 1000 से अधिक नक्सली हिंसा की घटनाएँ हुई थीं। यह 2024 में घट कर 374 पर आ गईं। इसके अलावा सुरक्षाबलों को 2010 में 1000 से अधिक जवान खोने पड़े थे। यह संख्या घट 2024 में घट कर 105 पर आ गई है।

शुगर मिलों और गुड़ भट्टी मजदूरों द्वारा फैलाई जा रही है गन्दगी

-बद्री प्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। एक ओर जहां केन्द्र से लेकर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाते हुए स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपये की राशि खर्च की जा रही हैं। मगर यह स्वच्छता अधिकारियों की उदासीनता के चलते जहां सिर्फ काग़ज़ों पर चलते देखी जा रही हैं तो दूसरी ओर सरकार द्वारा स्वच्छता के नाम पर खर्च की जा रही राशि सिर्फ बर्बादी होने के अलावा ओर कुछ साबित होते हुए दिखाई नहीं दे रहीं है। लगभग 07 वर्ष पहले ओडीएफ घोषित हो चुके जिले में अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनदेखी का परिणाम इस प्रकार से बन चुका हैं कि ओडीएफ घोषित जिला पूर्ण रूप से गन्दगी युक्त हो चुका है। जिसके चलते वर्तमान समय में सरकार द्वारा स्वच्छता के नाम पर चलाए जा रहे कार्यक्रम मात्र एक दिखावा साबित होने के साथ-साथ शासकीय धन की बर्बादी बन चुका हैं क्योंकि ओडीएफ घोषित जिला में शासन द्वारा गांव-गांव हर नागरिक के घरों में पक्के शौचालयों का निर्माण करने के साथ बाहर से आने वाले लोगों को गांव से लेकर कस्बों शहरों में शुलभ शौचालयों का निर्माण कराया गया। वहीं दूसरी ओर जिला में संचालित होने वाले शुगर मिलों से लेकर गुड़ भट्टी के संचालकों को बीते हुए वर्ष स्पस्ट रूप से आदेश जारी किया गया था। उनकी शुगर मिलों में काम करने के लिए बाहर से आने वाले कर्मचारियों, मजदूरों के लिए शौचालयों के उचित प्रबंध किए जाये और यदि मौके पर नहीं पाए गए तो कार्रवाई करने की बात कहीं गई है।

एम्स भोपाल में आंख से निकाला गया एक इंच लंबा जीवित परजीवी

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, संस्थान ने एक बार फिर चिकित्सा अनुसंधान और रोगी देखभाल के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता को साबित किया है। हाल ही में, एम्स भोपाल के नेत्र विज्ञान विभाग ने एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ सर्जिकल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिसमें एक मरीज की रेटिना से एक इंच लंबा परजीवी कीड़ा निकाला गया। यह उपलब्धि उन्नत नेत्र शल्य चिकित्सा में एम्स भोपाल की विशेषज्ञता को दर्शाती है और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की इसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

मध्य प्रदेश के रूसल्लीप निवासी 35 वर्षीय पुरुष मरीज को आंखों में बार-बार लाली और दृष्टि कमजोर होने की समस्या हो रही थी। उन्होंने कई चिकित्सकों से परामर्श लिया और स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स तथा टैबलेट्स का उपयोग किया, जिससे उन्हें केवल अस्थायी राहत मिली। जब उनकी दृष्टि और अधिक गिरने लगी, तो वे एम्स भोपाल पहुंचे, जहां उनकी आंख के कांचीय द्रव (विट्रियस जेल) में एक जीवित परजीवी कीड़ा पाया गया। मुख्य रेटिना सर्जन डॉ. समेंद्र करखुर, जिन्होंने इस सर्जरी का नेतृत्व किया, ने प्रक्रिया की जटिलता को समझाते हुए कहा कि आंख से एक बड़े और जीवित परजीवी को निकालना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। यह कीड़ा पकड़ने से बचने की कोशिश करता है, जिससे सर्जरी और भी मुश्किल हो जाती है। इसे सुरक्षित रूप से निकालने के लिए हमने उच्च-सटीकता वाली लेजर-फायर तकनीक का उपयोग किया, जिससे परजीवी को बिना आसपास की नाजुक रेटिना संरचनाओं को नुकसान पहुंचाए निष्क्रिय कर दिया गया। परजीवी को निष्क्रिय करने के बाद, हमने इसे विट्रियो-रेटिना सर्जरी तकनीक का उपयोग करके सफलतापूर्वक हटा दिया।

इस परजीवी की पहचान ग्नाथोस्टोमा स्पिनिजेरम के रूप में हुई, जो आंख के अंदर बहुत ही दुर्लभ रूप से पाया जाता है। अब तक दुनिया में केवल 3-4 मामलों में ही इस परजीवी लार्वा के आंख के विट्रियस कैविटी (कांचीय द्रव) में पाए जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। यह परजीवी कच्चे या अधपके मांस के सेवन से मानव शरीर में प्रवेश करता है और त्वचा, मस्तिष्क और आंखों सहित विभिन्न अंगों में प्रवास कर सकता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। डॉ. कर्कुर ने पुष्टि की कि मरीज अब स्वस्थ हो रहा है और जल्द ही उसकी दृष्टि में सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अपने 15 वर्षों के करियर में उन्होंने पहली बार इस प्रकार का मामला देखा और सफलतापूर्वक प्रबंधित किया।

स्मृति शेष

विरासत में मिले प्रोफेसर प्रेम बिहारी यदु को कुशाग्र बुद्धि के नैसर्गिक गुण

आकर्षक व्यक्तित्व, सहज स्वभाव, कुशाग्र बुद्धि के नैसर्गिक गुण प्रोफेसर प्रेम बिहारी यदु को विरासत में मिले थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पंडित दीनानाथ माडल स्कूल सीतावर्डी में हुई। स्नातक और स्नातकोत्तर एमए अंग्रेजी की डिग्री मारिस कालेज नागपुर से मिली। इनका जन्म 22 सितम्बर 1924 को सरायपाली में हुआ था। इनका विवाह 08 मई 1958 को सावित्री रानी जिला जालौन उप्र में सम्पन्न हुआ। आपने 1958 से 1962 तक रायगढ़ साइंस एण्ड आर्ट्स कॉलेज में अध्यापन किया। 1962 से 1965 तक राबर्टसन कालेज (वर्तमान महाकौशल महाविद्यालय) जबलपुर मध्यप्रदेश में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर रहे। इसी कॉलेज में आचार्य रजनीश दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे, तीन वर्षों तक आप दोनों एक ही स्टॉफ रूम में आसपास बैठकर अंग्रेजी में दर्शन शास्त्र पर चर्चा करते थे। इसी समय श्री रजनीश ने अध्यापन से अलग दर्शन शास्त्र का ही मार्ग चुन लिया। प्रोफेसर यदु को अध्यापन और छात्रों को विद्यादान देने में रुचि थी और वे कालेज से जुड़े रहे, किंतु अधिकांश समय उनका, पुस्तकालय में अध्ययन में ही गुजरता था। सन् 1965 में आपका स्थानांतरण साइंस कालेज रायपुर में हो गया। सिद्धांत वादी प्रोफेसर साहब पांच किलोमीटर दूर अपने बैरन बाजार स्थित आवास से कभी पैदल और कभी सायकिल में कालेज जाते थे। क्रिकेट व लॉन टेनिस में अत्यधिक रुचि होने के कारण कालेज में ,खेल-कूद अधिकारी बनाये गये। आपकी देख रेख में कालेज की टीम ने कई टूर्नामेंट जीते, जो भी छात्र शतक बनाता था आप उसे अपनी तनख्वाह से प्रोत्साहन पुरस्कार देते थे इसलिए छात्रों के बीच में अपने आकर्षक व्यक्तित्व और उदार हृदय के कारण बहुत लोकप्रिय थे। अंग्रेजी भाषा जिन छात्रों को बहुत कठिन लगती थी व जो भी जरूरतमंद छात्र होता उनको वे अतिरिक्त समय में निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते और उसे विषय में पारंगत कर देते थे।

बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अफसर पिता के पुत्र होने के कारण प्रोफेसर यदु को धन-संचय का कभी मोह नहीं रहा। आपको जीवन में असीम उदारता दयालुता और दूसरों की मदद करने की गहरी प्रतिबद्धता की संवेदना से भरा हुआ हृदय विरासत में मिला था मानवता की सेवा करने की वास्तविक इच्छा से प्रेरित होकर जरुरतमंदों को विशेष कर कितने ही बाढ़ पीड़ितों की निःस्वार्थ मदद की। आपने हजारों छात्रों को एक शिक्षक के रुप में सहानुभूति, विनम्रता और दृढ़ता पैदा करते हुये उनके चरित्र को आकार दिया। लम्बे अध्यापन काल में वे विभागाध्यक्ष के तौर पर कार्यरत होते हुए कभी छत्तीसगढ़ गढ़ कालेज बैरन बाजार तो कभी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर तो कभी परीक्षक के रूप में जाते रहे।तथा कई छात्राओं को MA इंग्लिश में स्नातकोत्तर डिग्री लेने में यथासंभव मदद की, इस प्रकार वे महिला सशक्तिकरण के जीवंत उदाहरण रहे हैं।गायत्री उपासक के रुप में वे अपनी पांचों पुत्रियों को गायत्री के पंचमुख मानते थे ओर कहते थे इन पांचों में विश्व बसा है। सभी को उन्होंने उच्चतम शिक्षा दिला कर अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचाया। पीबी यदु जी का जीवन निस्वार्थता, बुद्धिमता और दयालुता का उदाहरण है। उनकी विरासत उनके द्वारा छुए गए जीवन और उनकी शिक्षाओं के स्थाई प्रभाव में जीवित है आइए हम करुणा और आशा के उनके उदाहरण का अनुसरण करके उनकी स्मृति का सम्मान करें।

सम्पादकीय

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मोहन सरकर फिर लेगी कर्जा

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव की सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले 06 हजार करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। इस तरह अब तक मध्य प्रदेश पर 41,000 करोड़ रुपए लोन के रूप में बकाया है। तीन अलग-अलग किस्तों में यह लोन लिया जाएगा। एक लोन का भुगतान 12, दूसरे का 15 और तीसरे लोन का भुगतान 23 साल में किया जाएगा। इसके पहले 01 जनवरी को ही एमपी सरकार द्वारा पांच हजार करोड़ का लोन लिया गया था। बीते चार महीने में ही मध्य प्रदेश सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपए का लोन ले लिया है। अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सरकार दोबारा बड़ी रकम लोन के रूप में उठाने वाली है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए करोड़ों रुपए खर्च होने हैं। इसके चलते सरकार ने दोबारा लोन लेने की तैयारी कर ली है। अगर एक नजर सरकार के लोन लेने के इतिहास को देखें तो कई तारीखें इसमें दिखाई देती हैं। 23 जनवरी को 2500 करोड़ का कर्ज लिया गया। 06 फरवरी को 03 हजार करोड़ और 27 फरवरी को पांच-पांच हजार करोड़ रुपए के दो लोन लिए गए। 26 मार्च को 05 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया। 06 अगस्त को दो किस्तों में पांच हजार करोड़ का लोन और 27 अगस्त को 14 और 21 साल के लिए 05 हजार करोड़ रुपए का कर्ज। 24 सितंबर 2024 को फिर 2500-2500 करोड़ रुपए के कर्ज, दोनों ही कर्ज 12 साल और 19 साल की अवधि के लिए हैं। 08 अक्टूबर को 11 और 19 साल के लिए 05 हजार करोड़ का लोन। 26 नवंबर को स्टाक गिरवी रखकर सरकार ने 05 हजार करोड़ बाजार से उठाए। 24 दिसंबर को 5000 करोड़ रुपए का कर्जा सरकार ने लिया है।

उल्लेखनीय है कि, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अधोसंरचना विकास को गति देने के उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार से अधिक कर्ज लेने की अनुमति मांगी थी। सरकार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुपात में कर्ज सीमा को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने का आग्रह किया था। वर्तमान में राज्य को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत के अनुपात में कर्ज लेने की अनुमति है। मध्य प्रदेश सरकार ने अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह खर्च वर्तमान में 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष में 65,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की योजना है।

सियासी गहमागहमी

शिवराज के बेटे की शादी में भी चर्चा का विषय बना अध्यक्ष पद

पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटों की शादी नीलबड़ स्थित एक गार्डन से हुई। इस शादी में मध्यप्रदेश और देश के कई प्रमुख राजनेता व अतिथि पहुंचे। खास बात यह है कि इस शादी में भाजपा नेताओं के बीच चर्चा का विषय प्रदेश का अध्यक्ष पद का चुनाव था। हर जगह चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि आखिर किसके सिर पर प्रदेश अध्यक्ष पद का सेहरा बंधेगा। भले ही अभी सेहरा शिवराज सिंह चौहान के बेटों के सिर पर बंधा हो, लेकिन राजनैतिक सेहरा किसके सिर पर सजेगा इसको लेकर सभी चिंतित है। जानकारी के अनुसार वीडी शर्मा से लेकर नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री डॉ. यादव सभी एक दूसरे के चेहरों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके नाम की घोषणा आलाकमान करेगा। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि शायद वीडी शर्मा का कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है।

कमलनाथ ने दी भाजपा को चुनौती

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जहां एक तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में इस पर सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की मोहन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि एमपी में ओबीसी को आरक्षण देने के मामले पर राज्य सरकार का रवैया ढुलमुल है। उन्होंने इस संबंध में पोस्ट भी किया है। कमलनाथ ने बताया कि पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार की एक चूक से संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई है। इसका बड़ा कारण विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का पालन नहीं कराना, संवैधानिक संकट की परिधि में आता है। अब 2021 की स्थिति बन गई है, जिसमें 27 प्रतिशत आरक्षण लागू होता है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की ख़बर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है।

शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और 34 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक तथा 22 कांस्य पदक प्राप्त कर चौथा स्थान प्राप्त किया।

राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

कांग्रेस पार्टी की महिला स्टार प्रचारकों और अद्भुत लीडरशिप योग्य राजनेता हैं प्रियंका गांधी

समता पाठक/जगत प्रवाह

प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी हैं। जो लगभग हर चुनावों में कांग्रेस की स्टार प्रचारक के रूप में दिखाई देती हैं। कई बार प्रियंका के नाम का सुझाव कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिये भी दिया गया, लेकिन वे खुद कभी पार्टी की बागडोर हाथ में लेने के लिये आगे नहीं आयीं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का कार्यभार सौंपा गया। यूपी-ईस्ट का कांग्रेस महासचिव नियुक्त किया गया। इससे पहले वे प्रचारक व कैम्पेन मैनेजर के रूप में पार्टी को अपनी सेवाएं प्रदान करती रही हैं। अगर निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने मनोविज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की और फिर आगे चलकर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद बार-बार उन्हें राजनीति में आने के लिये प्रेरित किया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा से पर्दे के पीछे रह कर काम किया। लेकिन अब गांधी परिवार की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए वो राजनीति में पूरी तरह आ गई हैं।

वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका को यूपी-ईस्ट का महासचिव नियुक्त किया। यानी पूर्वांचल में पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियों की जिम्मेदारी प्रियंका पर होगी। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिये अमेठी व आस-पास के क्षेत्रों में प्रचार किया। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस का साथ दिया और बीच में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी तोड़ा, जिसके लिये पुलिस ने उनसे ऐसा नहीं करने के लिये अनुरोध किया। 2012 में उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान वे कांग्रेस की स्टार प्रचारक रहीं। उन्होंने इस बार अमेठी से बाहर जाकर सुल्तानपुर में भी प्रचार किया। 2009 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिये फिर से प्रचार किया। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने अमेठी-रायबरेली क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के लिये भरपूर प्रचार किया। 2004 में 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी के लिये प्रचार मैनेजर का काम किया और राहुल गांधी के चुनाव प्रचार को भी संभाला। प्रियंका की प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा मॉडर्न स्कूल से हुई। साल 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो प्रियंका को अपने भाई राहुल के साथ घर पर ही रह कर अपनी पढ़ाई करनी पड़ी। प्रियंका ने दिल्ली विश्वविद्यालय के जुड़े महिला कॉलेज जीजस एंड मैरी कॉलेज से मनोविज्ञान (साइकोलॉजी) विषय में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। साल 2010 में उन्होंने बौद्धिस्ट स्टडीज में मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट की। यही नहीं प्रियंका शौकिया तौर पर रेडियो संचालक (रेडियो जॉकी) का काम भी करती हैं। प्रियंका को हिन्दी साहित्य में भी गहरी रुचि है। वे बड़े चाव से हिन्दी कविताएं और कहानियां पढ़ती हैं। जब प्रियंका 13 साल की थीं तब एक दोस्त के घर पर पहली बार उनकी मुलाकात रॉबर्ट वाड्रा से हुई। उस समय रॉबर्ट प्रियंका के साथ ही स्कूल में पढ़ते थे। शुरुआत में वे दोस्त बने और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। रॉबर्ट एक बिनजेसमैन फैमिली से ताल्लुक रखते थे। प्रियंका ने खुद ही रॉबर्ट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आखिरकार दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शुरुआत में रॉबर्ट के पिता और गांधी परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं था लेकिन प्रियंका की जिद के कारण बाद में उन्हें राजी होना पड़ा। 18 फरवरी 1997 को प्रियंका ने रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली।

प्रियंका के स्वभाव, उनके हेयर स्टाइल और लुक को देखते हुए कांग्रेस समर्थक उनमें इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। पिछले काफी दिनों से उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने की मांग की जा रही थी लेकिन उन्होंने खुद को राजनीति से दूर रहने का फैसला किया था। प्रियंका ने कई बार कहा था कि उनकी प्राथमिकता उनकी फैमिली और उनके बच्चे हैं और वह राजनीति में नहीं आना चाहतीं। हालांकि, मां सोनिया और राहुल गांधी के चुनाव अभियान में पीछे से सहयोग जरूर करती थीं। सोनिया और राहुल के चुनाव अभियान के दौरान वे उनका प्रचार करते हुए भी देखी जाती थीं, लेकिन उनका प्रचार अभियान केवल अमेठी और रायबरेली संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित रहता था। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका, अपनी मां के चुनाव अभियान की कैम्पेन मैनेजर थीं। साल 2007 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका ने रायबरेली और अमेठी की दस विधानसभा सीटों पर अपना फोकस किया था। इस दौरान वे यहां दो सप्ताह तक रहीं और टिकट बंटवारे के साथ-साथ पार्टी की अंतर्कलह को सुलझाने की कोशिश की। ये प्रियंका की नेतृत्व क्षमता का ही प्रभाव था कि 2002 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की केवल 02 सीटों पर जीती कांग्रेस को 2007 में सात सीटों पर जीत मिली। पार्टी महासचिव बनने के बाद उनके नेतृत्व क्षमता की असली पहचान अब होगी

आइए इस परीक्षा के मौसम का जश्न मनाएं

-विजय गर्ग

परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, वैचारिक सीखने, तनाव प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करें और विकास के अवसरों के रूप में चुनौतियों को देखें। यह लेख उन सभी छात्रों को समर्पित है जिन्होंने शॉर्टकट पर कड़ी मेहनत और दृढ़ता को चुना है, सफलता के लिए सही मार्ग को अपनाया है। ये महान दिमाग हैं जो समझते हैं कि समर्पण और प्रयास उनके भविष्य को आकार देते हैं। हालांकि, हमारे परीक्षा योद्धाओं के लिए चीजों को प्रगति में लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अत्यधिक दबाव और तनाव का निर्माण हानिकारक हो सकता है, खासकर युवा, विकासशील दिमाग के लिए। कोने के चारों ओर बोर्ड परीक्षा और पहले से ही उलटी गिनती शुरू होने के साथ, बुजुर्ग तैयारी में डूबी युवा पीढ़ी को देखकर गर्व महसूस करते हैं। कई छात्र शीर्ष पदों और विशिष्टताओं को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। जो लोग ईमानदारी से प्रयास के साथ आधी रात के तेल को जलाते हैं, वे निस्संदेह सफलता की राह पर हैं। हालांकि, छात्रों को परीक्षा के मौसम को इस तरह से मनाना सीखना चाहिए जो बेहतर परिणाम देता है। परीक्षा से जुड़ा तीव्र दबाव कभी-कभी युवा दिमाग को अभिभूत कर सकता है, जिससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। बोर्ड परीक्षा, विशेष रूप से, छात्रों के बीच बढ़ी हुई चिंता पैदा करती है। यह अत्यधिक दबाव उनकी मानसिक भलाई को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके बजाय, छात्रों को तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इस अवधि को आत्मविश्वास और लचीलापन के साथ दृष्टिकोण करना चाहिए।

परीक्षा: एक साधन, एक अंत नहीं

परीक्षाएं हमारी शिक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, लेकिन वे केवल प्रगति का एक साधन हैं, एक अंतिम लक्ष्य नहीं। उनका असली उद्देश्य छात्रों को आगे बढ़ाने में मदद करना है, न कि उन्हें वापस पकड़ना। परीक्षा को एक अध्यादेश की तरह महसूस नहीं करना चाहिए बल्कि विकास का अवसर होना चाहिए। छात्रों को उन्हें एक भयभीत चुनौती के रूप में नहीं बल्कि अधिक उपलब्धियों की ओर एक कदम पत्थर के रूप में देखना चाहिए। यदि सही मानसिकता के साथ संपर्क किया जाता है, तो परीक्षा चिंता के बजाय सशक्तिकरण का स्रोत हो सकती है।

अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका

माता-पिता और शिक्षकों सहित बुजुर्ग, छात्रों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें बच्चों को सिखाना चाहिए कि कोई भी परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। कड़ी मेहनत और स्मार्ट काम के बीच अंतर महत्वपूर्ण है- जो छात्र कुशलता से अध्ययन करना जानते हैं वे किसी भी परीक्षा से आसानी से निपट सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस डिजिटल युग में, छात्रों को बुद्धिमानी से प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सीखना चाहिए। जबकि मोबाइल फोन और डिजिटल संसाधन सहायक हैं, अत्यधिक स्क्रीन समय उल्टा हो सकता है। इसके बजाय, मुद्रित पुस्तकें अक्सर केंद्रित सीखने के लिए अधिक प्रभावी साबित होती हैं।

रोट मेमोराइजेशन पर वैचारिक सीखना

छात्रों को रटने के संस्मरण पर वैचारिक स्पष्टता को प्राथमिकता देनी चाहिए। अवधारणाओं को गहराई से समझने से दीर्घकालिक प्रतिधारण होता है, जबकि यांत्रिक संस्मरण अक्सर भूल जानकारी में परिणाम होता है। सच्ची सीख विचारों को लोभी करने और उन्हें अपने शब्दों में प्रस्तुत करने से आती है। जो लोग शुरू से ही एक मजबूत नींव के साथ अध्ययन करते हैं, उन्हें परीक्षा आने पर डर नहीं लगता है।

शिक्षा: मार्क्स की दौड़ से परे

शिक्षा ग्रेड और डिग्री के लिए एक पागल दौड़ नहीं है। इसका असली उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, नई अवधारणाओं को समझना और उत्कृष्टता की खेती करना है। जब छात्र उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सफलता स्वाभाविक रूप से होती है। अंतिम-मिनट शॉर्टकट की खोज करने के बजाय, उन्हें सीखने के लिए एक स्थिर, अच्छी तरह से संरचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

परीक्षा के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण

छात्रों को सकारात्मक और शांत मानसिकता के साथ परीक्षा के मौसम का आनंद लेना सीखना चाहिए। यदि आप अच्छी तरह से तैयार हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। यदि आपको संदेह है, तो अपनी क्षमता पर भरोसा करें। और अगर आप बिना तैयारी के महसूस करते हैं, तो अनुभव को अपनाएं और इससे सीखें। जैसा कि कहावत है: "सर्वश्रेष्ठ के लिए आशा है लेकिन सबसे बुरे के लिए तैयार रहें यहां तक कि असफलताओं से भी डरना नहीं चाहिए- वे अधिक सफलता के लिए पत्थर बढ़ा रहे हैं। जैसा कि किसी ने समझदारी से कहा, "यदि आप कोशिश करते हैं और असफल होते हैं, तो फिर से प्रयास करें। असफल बेहतर।" गलतियों से सीखना लचीलापन और भविष्य की सफलता के लिए एक मजबूत नींव बनाता है।

परीक्षा तनाव पर काबू पाना

परीक्षा तनाव अक्सर घबराहट की ओर जाता है। यहां तक कि अच्छी तरह से तैयार छात्र कभी-कभी अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, डर है कि वे महत्वपूर्ण जानकारी भूल सकते हैं। हालांकि, ये भावनाएं अक्सर निराधार होती हैं और बस चिंता का परिणाम होती हैं। कुंजी आराम करना और अपनी तैयारी पर भरोसा करना है। डर और तनाव को कभी भी मन को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, छात्रों को अपने विचारों को बुद्धिमानी से प्रबंधित करना चाहिए और हर परीक्षा का सामना तेज दिमाग और आत्मविश्वास से करना चाहिए। उन लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो प्रभावी ढंग से सीखना, तनाव का प्रबंधन करना और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करना जानते हैं। तो, आइए इस परीक्षा के मौसम को आत्मविश्वास, सकारात्मकता और इस विश्वास के साथ मनाएं कि हर प्रयास एक उज्जवल भविष्य की ओर गिना जाता है।

मुफ्त की रेवड़ियां : परजीवियों का तैयार होता एक वर्ग

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

जीव-विज्ञान की भाषा में परजीवी ऐसे जीवाणु या कीटाणु होते हैं, जो किसी दूसरे जीव के अंदर रहकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार की मुफ्त रेवड़ियों पर आश्रित ऐसे ही लोगों और सरकार पर कटाक्षपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा नगद धनराशि एवं निशुल्क सुविधाएं देने के वादों पर कहा है कि राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों को मुख्य धारा में लाने की बजाय, क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे? ये लोग मुफ्त राशन और धन मिलने से काम करने को तैयार नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी शहरी इलाकों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी मांग पर सुनवाई के दौरान की है। अदालत की इस चिंता को राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में वाजिब कहा जा सकता है। क्योंकि मुफ्त राशन और धन मिलने से लोग आलसी और निकम्मे तो हो ही रहे हैं, इनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार 81 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन तो दे ही रही है, राज्य सरकारें चुनाव के ठीक पहले लाडली बहनाओं को प्रतिमाह 1250 से लेकर 3000 रुपए तक नगदी का लालच देकर मतदाता को लुभा रहे हैं। नतीजतन मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग मुफ्त की रेवड़ियों के लालच में मतदान करने लगा है। यह स्थिति संवैधानिक लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।

निर्वाचन लोक-पर्व के अवसर पर मुफ्त में तोहफे बांटे जाने की घोषणाएं सभी राजनीतिक दल बढ़-चढ़कर करते रहे हैं। हालांकि निर्वाचन के बाद ज्यादातर वादे फरेब साबित होते हैं। बावजूद मतदाता को इस प्रलोभन में लुभाकर राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपना स्वार्थ साधने में सफल हो जाते हैं। परंतु अब सर्वोच्च न्यायालय ने इन चुनावी रेवड़ियां बांटे जाने पर गंभीर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुफ्त के इन उपहारों पर लगातार चिंता जताते रहे हैं। परंतु भाजपा भी चुनावों में रेवड़ियां बांटने के वादों से पीछे नहीं रही। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा की जीत के कारणों में इन वादों की भी अहम भूमिका रही है। भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने भी मुफ्त के वादों पर रोक के लिए न्यायालय में याचिकाएं लगाई हुई हैं। उन्होंने ऐसे दलों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। इन वादों पर रोक इसलिए जरूरी है, क्योंकि इन लोक-लुभाव वादों के दो तरह के प्रभाव देखने में आते हैं। एक तो ये मतदाताओं के निष्पक्ष निर्णय को प्रभावित करते हैं और दूसरे, इन्हें पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब चुनाव नीतियों और कार्यक्रम की बजाय प्रलोभनों का फंडा उछालकर लड़े जाने लगे हैं। राजनेताओं की दानवीर कर्ण की यह भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ों में मट्ठा घोलने का काम कर रही है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए मतदाता को बरगलाना आदर्श चुनाव संहिता को ठेंगा दिखाने जैसा है। सही मायनों में वादों की घूस से निर्वाचन प्रक्रिया प्रदूषित होती है, इसलिए इस घूसखोरी को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाना जरूरी है। वैसे भी इन वादों की हकीकत जमीन पर उतरी होती तो पंजाब में 7000 किसानों ने आत्महत्या न की होती? क्योंकि पंजाब में किसान कल्याण के सबसे ज्यादा वादे अकाली दल ने सरकार में रहते हुए किए थे। अफलातूनी वादों के उलट हकीकत में अब ज्यादा जरूरत शासन-प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की है। यह वादा ज्यादातर राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्र से हमेशा गायब रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक समय जरूर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की राह पर चली थी, लेकिन अपने तीसरे कार्यकाल में शराब नीति में घोटाले और शीशमहल जैसे राजसी वैभव में डूब गई। आप ने बिजली दरें 50 फीसदी कम करने और हर परिवार को रोजाना 700 लीटर पानी मुफ्त मुहैया कराने के बुनियादी वादों के साथ चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। 2025 के विधानसभा चुनाव में आर्थिक स्थिति की बदहाली और भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल की हार के प्रमुख कारण बने।

देश में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने निर्धन परिवारों को मुफ्त में एक बत्ती कनेक्शन देने के वादे के साथ यह शुरूआत आठवें दशक में की थी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं जयललिता ने तो चुनावी वादों का इतना बड़ा पिटारा खोल दिया था कि यह मामला जनहित याचिका के जरिए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया था। इस याचिका में अन्नाद्रमुक की चुनावी घोषणा को भ्रष्ट आचरण मानते हुए असंवैधानिक ठहराने की मांग की गयी थी, लेकिन न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी। उस समय न्यायालय ने दलील दी थी कि घोषणा-पत्रों में दर्ज प्रलोभनों को भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता है। चुनाव का नियमन जनप्रतिनिधित्व कानून के जरिए होता है और उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत इसे गैर कानूनी या भ्रष्ट कदाचरण ठहराया जा सके। न्यायालय ने लाचारगी प्रगट करते हुए कहा था कि इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लिहाजा इस मसले पर विचार कर कारगर निर्णय लेने का कोई कदम विधायिका ही उठा सकती है। अलबत्ता अदालत ने निर्वाचन आयोग को जरुर निर्देश दिया था कि वह चुनावी घोषणा-पत्रों को मर्यादित करने की दृष्टि से अतिवादी व लोक-लुभावन घोषणाओं को रेखांकित करे, जिससे आदर्श चुनाव संहिता का पालन हो सके।

इस परिप्रेक्ष्य में दुविधा यह है कि राजनीतिक दलों पर आयोग का अनुशासनात्मक नियंत्रण निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद होता है, जबकि ज्यादातर घोषणा-पत्र इस अधिसूचना के पहले जारी हो जाते हैं और कई वादे तो नेता चुनावी आमसभाओं में आचार संहिता का मखौल उड़ाते हुए भी कर डालते हैं। यहां तक कि अल्पसंख्यक मुस्लिम और सवर्ण ब्राह्मणों तक को आरक्षण देने का वादे किए जाते रहे हैं। जिस पर भी विडंबना है कि आदर्श निर्वाचन संहिता के तहत न तो कोई दंडात्मक कानून है और न ही इसकी संहिताओं में वैध-अवैध की अवधारणाएं परिभाषित हैं। आयोग यदि संहिता को लागू कर पाता है तो इसलिए कि राजनीतिक दल उसका सहयोग करते हैं और जनमत की भावना आयोग के पक्ष में होती है। तय है दल यदि आयोग के साथ असहयोग करने लग जाएं तो आयोग हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाएगा। वैसे भी आयोग की जवाबदेही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की है, न कि दलों के चुनावी मुद्दे तय करने की? बावजूद आयोग मामले संज्ञान में लेता है और उम्मीदवार को चेतावनी भी देता रहता है। लेकिन उम्मीदवार जानते हैं कि उनकी उम्मीदवारी को तत्काल खारिज करने का कोई अधिकार आयोग के पास नहीं है, इसलिए वे बेपरवाह रहते हैं।

इन विरोधाभासी हालातों से शीर्ष न्यायालय परिचित है। इसलिए वह मुफ्त की घोषणा पर टिप्पणी कर शांत रह जाती है। दरअसल ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श कर कानून बनाने का अधिकार विधायिका को ही है। यहां विडंबना है कि विधायिका और दल अंततः एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रलोभन के जिन वादों के मार्फत मतदाता को बरगलाकर दल सत्ता के अधिकारी हुए हैं, उन वादों को घोशणा-पत्र में नहीं रखने का कानून बनाकर अपने ही हाथों से, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की गलती क्यों करेंगे? यहां सवाल यह भी उठता है कि दल जो घोषणाएं करते हैं उनका लाभ वर्ग-भेद के बिना जरूरतमंदों को मिलता है। फिर चाहे वह छात्रवृत्ति हो, लैपटॉप हो, साइकिल हो अथवा टीवी? मुफ्त बिजली हो, लाडली बहनों को नगद धनराशि हों या सस्ता राशन, इसमें कोई जातीय या वर्गीय भेद नहीं किया जाता। बीपीएल की सूची में आने वाले सभी जरूरतमंद के हकदार होते हैं। ऐसी स्थिति में मुफ्त उपहारों को विभाजित करना एक जटिल प्रक्रिया है। हां, जातीय अथवा अल्पसंख्यक के आधार पर आरक्षण की घोषणा की जाती है तो इस स्थिति को जातीय अथवा सांप्रदायिक भेद की स्थिति माना जा सकता है ? 81 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज देने की सुविधा को भरे पेट वाले गुलछर्रे उड़ा रहे लोग सरकारी धन का दुरुपयोग मानते हैं। जबकि एक कल्याणकारी राज्य के वंचित तबके के लिए ये सुविधाएं अनिवार्य जरूरत भी हैं। ऐसे में इन्हें एकाएक घूस या लालच नहीं कहा जा सकता? अलबत्ता यह तथ्य जरूर सही है कि प्रलोभन मतदाता की नीयत को प्रभावित करता है और वह व्यापक सामाजिक हित की बजाय व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेने को विवश हो जाता है। जाहिर है, यह एक गंभीर मसला है और न्यायालय इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई ऐसा हल जरूर निकले, जो सर्वमान्य होने के साथ लोक कल्याणकारी भी साबित होगा।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश और विदेश के मेहमानों के स्वागत में 1500 करोड़ लुटायेगी मोहन सरकार

(पेज 1 से जारी)

मैंने पहले भी प्रदेश के मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल का भी छापा था, जहां मोहन यादव ने अधिकारी नहीं पदस्त करने के कारण प्रदेश में 50 दिनों तक उद्योग नहीं लगने दिया, ऐसे में आश्चर्य नहीं होगा कि काग़जों में तो निवेश दिखाया जाएगा पर वास्तविक जमीन पर कुछ उतरने वाला नहीं है। दिक्कत यह है कि मोहन यादव का विजन सिर्फ पैसा कमाने का रहा है, ना उनका दायरा बड़ा था, ना व्यापक। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने के बाद पिछले सवा साल में कोई खास उपलब्धि भी हासिल नहीं की है। ऐसे में ऐसा दिखावा तो करना ही पड़ेगा भले ही प्रदेश का दिवाला निकल जाये।

आखिर इतना खर्च कर क्या होगा फायदा?

विशेषज्ञों की मानें तो जब मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले एक साल में सात संभागीय मुख्यालयों में क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव आयोजित किये और इतनी बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त किये तो फिर जीआईएस की आवश्यकता क्यों पड़ी। जीआईएस का आयोजन कहीं न कहीं एक ओर यह साबित करता है कि सरकार और मुख्यमंत्री यादव को ने क्षेत्रीय समिट के नाम से जो भी घोषणाएं निवेश प्राप्ति हो लेकर की है वह सभी खोखली हैं और अब उन पर पर्दा डालने के लिये जीआईएस के आयोजन की श्रृंखला शुरू की है। एक बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर जीआईएस जैसे इतने बड़े आयोजन की आवश्यकता क्यों है। आखिर सरकार जनता के टैक्स के करोड़ों रुपयों को इस तरह से आयोजन के नाम पर क्यों बर्बाद कर रही है। आखिर जनता के पैसों की बर्बादी का यह सिलसिला कब रुकेगा।

1500 करोड़ खर्च करने की योजना

चर्चा है इस समिट में प्रधानमंत्री पहली बार भोपाल में आयोजन के एक दिन पहले यहां पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी पूरी मुस्तैदी से काम में जुटे हुए हैं। अधिकारियों और नेताओं सहित मंत्रियों की इतनी मुस्तैदी देख आमजन होने के नाते एक ख्याल बार-बार मन में आता है कि अगर किसी वीआईपी व्यक्ति के आने से शहर में साफ-सफाई, सड़कों का निर्माण सहित सौंदर्यीकरण के कार्यों को गति मिलती है तो यह देख लगता है कि भले प्रदेश में निवेश धरातल पर उतरे या नहीं लेकिन वीआईपी के आने से शहर की सूरत जरूर बदल जाती है। इन सभी कार्य में सरकार लगभग 1500 करोड़ रुपये फूंकने के लिये तैयार है। मंत्रालय के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार भोपाल में हो रही इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के लिये मोहन यादव ने लगभग 1500 करोड़ो रुपये फूंकने की योजना बनाई है। कुल मिलाकर अपने आप में भव्यता लिये इस आयोजन में सरकार 1500 करोड़ रुपये सिर्फ अतिथियों के स्वागत, सत्कार, भोजन, प्रबंधन, शहर की सुंदरता सहित उनके आव-भगत में खर्च करेगी। भोपाल में 30 करोड़ रूपए की लागत से सड़कों की मरम्मत और शहर के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है।

नगर निगम का 50 प्रतिशत से अधिक बजट निपटाया

सूत्रों के अनुसार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन पर अंतिम फैसला होने के बाद ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया और अधिकारियों ने भी स्वच्छता और सुंदरता सहित पीडब्ल्यूडी और निगम के साथ मिलकर 100 करोड़ से अधिक के कार्यों को अंतिम रूप देने की योजना पर फैसला किया।

एयरपोर्ट से बोर्ड ऑफिस तक होगा सौंदर्यीकरण

राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को व्यापक रूप से संवारा जाएगा। व्यू कटर, एप्रोच रोड, बोर्ड और शेड के नवीनीकरण पर 71 लाख रुपये खर्च होंगे। एयरपोर्ट से बोर्ड ऑफिस तक की सड़क पर गमले, फूल और सजावट पर 73 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

जल संकट मानव निर्मित संकट है या प्रकृति का प्रकोप

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

जल जीवन का आधार है, लेकिन आज दुनिया भर में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह संकट केवल प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही और अनियंत्रित उपभोग की देन भी है। बदलते मौसम, बढ़ती जनसंख्या और जल संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने इस समस्या को और अधिक गहरा दिया है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाली पीढ़ियों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ेगा। जल की एक बूंद तो ऐसी पूंजी है जिसे कमाया नही जा सकता। ऐसे में इसका संरक्षण ही इसका निर्माण है।

जल संकट के कई प्राकृतिक कारण हैं, जिनमें मानसून की अनिश्चितता, सूखा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। भारत जैसे देश में बारिश के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखा गया है। कभी अत्यधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कभी सूखे के कारण खेती प्रभावित होती है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियरों का पिघलना भी जल संकट को बढ़ावा दे रहा है, जिससे नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है। अनेक नदियाँ, जो कभी साल भर बहा करती थीं, अब मौसमी बन गई हैं। पश्चिमी भारत के कई इलाके वर्षा की कमी से ग्रस्त हैं, वहीं पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में अतिवृष्टि की समस्या देखी जा रही है। इस असमानता के कारण जल संसाधनों का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जल संकट का सबसे बड़ा कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं। इसे एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। लॉकडाउन के दौरान जब मानव गतिविधियां सीमित हो गई थीं और मानव का प्रकृति में हस्तक्षेप कम हो गया था, तब स्वच्छ जल की श्रोत, नदियों की TDS (जल की घुलित अशुद्धियों) की रीडिंग में सुधार आ गई थी। प्रदूषण पर नियन्त्रण लगते ही शुद्ध जल प्राप्त होने लगे थे। जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की मांग कई गुना बढ़ गई है, लेकिन इसके संरक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। उद्योगों द्वारा जल का अत्यधिक दोहन और जलाशयों में अपशिष्ट छोड़ना जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है। शहरीकरण और कंक्रीटीकरण से भूजल पुनर्भरण की दर में कमी आई है। गाँवों में कुओं और तालाबों का महत्व घटता जा रहा है, जिससे सतही जल स्रोत लुप्तप्राय हो रहे हैं। इसके अलावा, किसानों द्वारा जल-गहन फसलों की खेती और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का अभाव जल संकट को और गहरा बना रहा है।

भारत में भूजल का अत्यधिक दोहन चिंता का विषय बन चुका है। कई क्षेत्रों में जलस्तर खतरनाक रूप से नीचे गिर चुका है, जिससे किसानों और आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। बोरवेल और ट्यूबवेल का अंधाधुंध उपयोग जल संकट को और बढ़ा रहा है। वर्षा जल संचयन जैसी पारंपरिक विधियों को छोड़कर हम आधुनिकता की दौड़ में जल संरक्षण को नजरअंदाज कर रहे हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत में भूजल का दोहन इसी गति से जारी रहा, तो 2050 तक देश के कई हिस्से पूरी तरह जलविहीन हो सकते हैं। यह संकट केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं, बल्कि महानगरों में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। शहरीकरण की तीव्र गति ने जल संकट को और विकराल बना दिया है। महानगरों में जल की मांग अत्यधिक बढ़ गई है, लेकिन उपलब्ध संसाधन इस मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। कई शहरों में पाइपलाइनों से पानी का रिसाव और बर्बादी आम समस्या बन चुकी है। वहीं, जल वितरण में असमानता के कारण गरीब वर्ग को स्वच्छ जल प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में हर साल गर्मियों के दौरान जल संकट विकराल रूप धारण कर लेता है। पिछले साल गर्मियों में बंगलूरू शहर सुर्खियों में रहा था। कारण था जल संकट। दिल्ली व अन्य महानगरों में जल आपूर्ति की समस्या के कारण लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे पानी की कीमतें बढ़ जाती हैं और असमानता बढ़ती है। कृषि क्षेत्र में जल संकट का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत में लगभग 80% पानी कृषि कार्यों में उपयोग होता है, लेकिन सिंचाई की पारंपरिक विधियों और जल प्रबंधन की कमजोरियां समस्या को और गंभीर बना रही हैं। धान और गन्ने जैसी फसलों की अधिक खेती, जो अत्यधिक पानी की मांग करती हैं, जल संकट को और बढ़ा रही हैं। यदि किसानों को जल-संरक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाए और सूखा-रोधी फसलों को प्रोत्साहित किया जाए, तो इस संकट को कम किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर तकनीकों के माध्यम से जल के अपव्यय को रोका जा सकता है।

सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे 'अटल भूजल योजना', 'जल शक्ति अभियान' हर घर जल और 'नमामि गंगे'। इन प्रयासों का उद्देश्य हर घर नल पहुंचाना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और जल प्रबंधन को सुधारना है। कई राज्यों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया गया है, लेकिन इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। सरकार के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों और नागरिकों को भी जल संरक्षण के लिए आगे आना होगा। जल प्रबंधन की पारंपरिक विधियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के हिवरे बाजार गाँव और राजस्थान के अलवर जिले में जल संरक्षण के प्रभावी उदाहरण देखे गए हैं, जिन्हें अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।

जल संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को जल संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी होगी। वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई, जल पुनर्चक्रण और भूजल पुनर्भरण जैसी तकनीकों को अपनाकर हम इस संकट को कम कर सकते हैं। इसके अलावा, जल उपयोग में संयम और जागरूकता अभियान चलाकर आम जनता को इसकी गंभीरता समझाने की आवश्यकता है। स्कूलों और कॉलेजों में जल संरक्षण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि बचपन से ही जल बचाने की आदत विकसित हो सके। विभिन्न देशों में जल संरक्षण के लिए अपनाए गए उपायों से भी प्रेरणा ली जा सकती है। इजरायल में जल पुनर्चक्रण की उन्नत तकनीकें अपनाई गई हैं, जिससे वहाँ जल संकट लगभग समाप्त हो चुका है। जल संकट का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामूहिक जागरूकता और प्रयासों की आवश्यकता है। यह संकट केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि हमारी लापरवाही का परिणाम है। यदि समय रहते हम जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते तो भविष्य में पानी की कमी हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसलिए, हमें आज ही जल बचाने का संकल्प लेना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकें।

वर्चुअल नहीं वास्तविक जीवन में खोजें खुशी

मोबाइल को अपना सहायक बनाएँ, स्वामी नहीं

सोशल मीडिया के जाल में फंसकर वास्तविक रिश्ते छूट रहे पीछे

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में, हम सब वर्चुअल दुनिया में खो से गए हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और अनगिनत ऐप्स के जाल में फंसकर, हमने वास्तविक जीवन के रिश्तों और अनुभवों को पीछे छोड़ दिया है लेकिन, क्या कभी सोचा है कि इस वर्चुअल दुनिया में मिलने वाली खुशी कितनी अस्थायी है? एक लाइक, एक कमेंट, या एक गेम जीतने के बाद मिलने वाली खुशी पल भर में गायब हो जाती है। असली संतुष्टि तो वास्तविक जीवन में है, अपनों के साथ बिताए पल, दोस्तों के साथ हंसी-मजाक, और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में।

आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे है जहाँ तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट- ये सब हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, सूचना और मनोरंजन के स्रोत है लेकिन, क्या हो अगर ये सहायक हमारे स्वामी बन जाएँ? क्या हो अगर हम वर्चुअल दुनिया में इतने खो जाएँ कि वास्तविक जीवन के रिश्तों, अनुभवों और खुशियों को भूल जाएँ? मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से हमारे मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आजकल, बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं। ऑनलाइन क्लास, सोशल मीडिया, गेम्स- सब कुछ मोबाइल पर उपलब्ध है। लेकिन, इस वर्चुअल दुनिया में खोने से हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पिड़पिड़ापन, सिरदर्द, आँखों की समस्या, अनिद्रा- ये सब मोबाइल की लत के दुष्परिणाम है। मोबाइल की लत का मतलब है मोबाइल के बिना असहज महसूस करना। आज हम इतने आदी हो गए हैं कि मोबाइल के बिना हम अधूरे से महसूस करते हैं। यह लत हमारे जीवन को हर तरह से प्रभावित कर रही है।

बढ़ रहा मानसिक तनाव:

* **तुलना:** सोशल मीडिया पर दूसरों की दिखावटी जिंदगी देखकर हम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हो जाते हैं।
* **एकाग्रता में कमी:** मोबाइल के कारण हमारी एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है।
* **रिश्तों में दरार:** परिवार और दोस्तों के साथ आमने-सामने की बातचीत कम हो जाती है।
* **गलतफहमी:** सोशल मीडिया पर गलतफहमी और विवाद बढ़ जाते हैं।
* **समय की कमी:** मोबाइल में व्यस्त रहने के कारण रिश्तों के लिए समय नहीं मिल पाता है।
* **चिंता:** लगातार नोटिफिकेशन और मैसेज चेक करने की आदत से चिंता और तनाव बढ़ता है।
* **नींद में कमी:** रात को देर तक मोबाइल इस्तेमाल करने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

यह प्रयास होंगे कारगर

* **समय सीमा निर्धारित करें:** मोबाइल के उपयोग के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें और उसका पालन करें। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आप इसके आदी हो जाएंगे।
* **नोटिफिकेशन बंद करें:** अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करें ताकि बार-बार मोबाइल देखने की इच्छा न हो। केवल जरूरी नोटिफिकेशन्स ही चालू रखें।
* **सोशल मीडिया से दूरी:** सोशल मीडिया पर कम समय बिताएँ और वास्तविक जीवन में लोगों से जुड़ें। सोशल मीडिया की तुलना में वास्तविक रिश्तों पर ध्यान दें।
* **आउटडोर गतिविधियों में भाग लें:** प्रकृति में समय बिताएँ, खेलें, व्यायाम करें। ताजी हवा और धूप आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं।
* **परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएँ:** उनके साथ बातचीत करें, हँसें, खेलें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आमने-सामने की बातचीत बहुत जरूरी है।
* **अपने शौक पूरे करें:** किताबें पढ़ें, संगीत सुनें, पेंटिंग करें, या जो भी आपको पसंद हो। अपने शौक के लिए समय निकालकर आप तनाव कम कर सकते हैं और खुशी महसूस कर सकते हैं।
* **मोबाइल-मुक्त समय:** दिन में कुछ समय मोबाइल से दूर रहें। खासकर सोते समय और भोजन करते समय मोबाइल का उपयोग न करें।
* **मोबाइल-मुक्त क्षेत्र बनाएं:** घर में कुछ ऐसे क्षेत्र बनाएं जहाँ मोबाइल का उपयोग न हो, जैसे कि बेडरूम और डाइनिंग रूम। यह आपको मोबाइल से दूर रहने में मदद करेगा।
* **बच्चों के लिए रोल मॉडल बनें:** बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं, इसलिए उनके सामने मोबाइल का कम उपयोग करें। उन्हें मोबाइल के सही उपयोग के बारे में सिखाएं और उनके साथ समय बिताएँ।
* **अपने बच्चों को मोबाइल के सही उपयोग के बारे में सिखाएं:** उन्हें स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करने और ऑनलाइन खतरों से अवगत कराएं। बच्चों को मोबाइल के सुरक्षित और सही उपयोग के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है।
* **खुद के लिए समय निकालें:** हर दिन कुछ समय निकालकर आराम करें और अपने विचारों पर ध्यान दें। मेडिटेशन या योग करने से आपको तनाव कम करने में मदद मिलेगी।
* **मोबाइल का सकारात्मक उपयोग करें:** ज्ञान प्राप्त करने, नए लोगों से जुड़ने और रचनात्मक बनने के लिए मोबाइल का उपयोग करें। मोबाइल को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें, न कि अपनी जिंदगी का केंद्र बनाएं।

मोबाइल एक उपकरण है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए, न कि इसके द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। वर्चुअल दुनिया हमें कई सुविधाएं देती है, लेकिन यह हमें वास्तविक जीवन से दूर भी ले जा सकती है। हमें याद रखना होगा कि असली खुशी और संतुष्टि हमारे आसपास के लोगों और अनुभवों में ही छुपी है। आइए, आज से ही एक नई शुरुआत करें। मोबाइल को अपना सहायक बनाएँ, स्वामी नहीं। संकल्प लें कि हम वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन को अपनाएंगे और उसमें छुपी खुशियों का आनंद लेंगे

खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन और भंडारण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देशानुसार खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ संपूर्ण जिले में संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। आर.टी.ओ. और खनिज विभाग नर्मदापुरम द्वारा बानापुरा सिवनी मालवा, तहसील सिवनी मालवा में छापेमारी की गई। इस दौरान 06 डंपर क्रमांक MP47 ZD6777, MP10ZE9993, MP09HJ2089, MP47G0473, MP47ZD1026, और MP47Z C5783 को रेत खनिज का ओवर लोड परिवहन करते हुए पकड़ा गया। इन डंपरों को तत्काल जब्त कर पुलिस थाना सिवनीमालवा, तहसील सिवनीमालवा की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखा गया है। इस कार्यवाही में जिला खनिज अधिकारी दिवेश मरकाम, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नर्मदापुरम निशा चौहान, खनिज निरीक्षक पिंकी चौहान और होमगार्ड बल उपस्थित थे। जप्त किए गए वाहनों के खिलाफ मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्यवाही की जा रही है। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान जांच टीमें लगातार सिवनीमालवा, पगड़ाल, बाबरी, धरमकुंडी और अन्य स्थानों पर गस्त करती रहीं। यह कार्रवाई देर रात तक जारी रही, जिसमें 6 ओवर लोड डंपर जप्त किए गए, जो नर्मदापुरम जिले से रेत का अवैध परिवहन कर रहे थे और इसे हरदा, खंडवा, खरगौन और इंदौर जैसे जिलों में भेजा जा रहा था। सभी डंपरों को सिवनीमालवा थाने में खड़ा कर दिया गया है, और आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कबड्डी स्पर्धा में एसबीआई इन्दौर प्रथम व जयस क्लब बैतूल दूसरे पायदान पर

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में जयस संस्था के तत्वावधान में दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों व शहरों की करीब 40 टीमों ने हिस्सा लिया आयोजन के दौरान सैकड़ों कबड्डी प्रेमी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में खिलाडियों ने भी खेल का उम्दा प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में अतिथि विधायक अभिजीत शाह जप उपाध्यक्ष अनिल वर्मा युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल जायसवाल जयस जिलाध्यक्ष राकेश काकोडिया ब्लाक अध्यक्ष विनोद पथ रामेश्वर भुवे एवं विधायक प्रतिनिधि ओमप्रकाश मिश्रा सहित आयोजन समिति जयस संगठन के समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। पांच स्थानों पर आई टीमों को पुरस्कृत किया। कबड्डी प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के विभिन्न संभागों की करीब 40 टीमों ने हिस्सा लिया। फायनल मुकाबला एसबीआई इन्दौर व जयस क्लब बैतूल के बीच खेला गया, इसमें एसबीआई इन्दौर विजेता बन प्रथम स्थान पर रही, जिसे 21 हजार रुपए प्रदान किए दूसरे स्थान पर जयस क्लब बैतूल की टीम रही, जिसे 16 हजार रुपए तीसरे स्थान पर नर्मदा खेल एकेडमी टिमरनी रही, जिसे 11 हजार रुपए चतुर्थ स्थान पर गाडरवाड़ा टीम रही, जिसे 07 हजार रुपए पांचवें स्थान पर राजरानी टीम हरदा रही, जिसे 4100 रूपए नगद राशि प्रदान की गई।

20 वर्षों तक प्रधानमंत्री बने रहने की भविष्यवाणी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य महर्षि परेश दानी काशी पहुंचे

-अमित राय

जगत प्रवाह. वाहाणसी। गुजरात के अहमदाबाद निवासी विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्विद महर्षि डॉ. परेश दानी प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान के बाद काशी पहुंचे। पीस वर्ल्ड मिशन विश्व धर्म काउन्सिल के चेयरमैन एवं ज्योतिषाचार्य डॉ. दानी गंगा स्नान के बाद श्रीकाशी विश्वनाथ, काल भैरव और संकटमोचन महाराज का दर्शन पूजन किया। धर्मपत्नी संगीता दानी के साथ काशी पहुंचे महर्षि दानी ने भदैनी स्थित लोलार्केश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर विश्व शांति और भारत के खुशहाली के लिए कामना की।

बताते चलें कि ज्योतिर्विद महर्षि डॉ. परेश दानी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेन्द्र दामोदरदास मोदी के लिए 20 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहने की भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हुई। समय-समय पर ज्योतिर्विद दानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी को ज्योतिषीय परामर्श भी देते रहते हैं। डॉ. दानी विश्व के अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बंगलादेश, नेपाल आदि में बराबर ज्योतिष प्रचार हेतु यात्राएं किया करते हैं। सभी देशों की अनेक ज्योतिष संस्थाओं ने आपको पुरस्कृत किया है।

विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का हुआ जगह जगह भव्य स्वागत

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी। मध्यप्रदेश सरकार के विपक्ष के नेता उमंग सिंघार देवरी प्रवास पर रहे, जहाँ दमोह से होते हुए देवरी विधानसभा के झमारा व रमखिरिया पहुंचे, जहाँ अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोगों से मुलाक़ात कर उनकी समस्या सुन भाजपा सरकार पर आदिवासी वर्गों पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां बिजली, पानी आदि शासन कि कोई योजना नहीं मिल रही। सरकार सिर्फ दिखावा करती है। उन सभी की मांग को लिखित रूप से लेकर विधानसभा में बात रखने का सभी को आश्वासन दिया। वहीं महाराजपुर पहुंचने पर देवरी ब्लॉक अध्यक्ष आशीष बाबा राजोरिया ने सैकड़ों की संख्या में गाजे बाजे, फूलमाला, श्रीफल के साथ भव्य स्वागत किया। देवरी नगर आगमन पर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव पाण्डेय ने नगरपालिका तिराहा पर फूलमाला से अपनी टीम के साथ स्वागत किया। देवरी के कांग्रेस नेता शुभम मिश्रा ने अपनी होटल पर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष के काफ़ले के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं प्रशासन के वाहनों का काफ़ला रहा।

पटेल वार्ड पार्षद ने दिया ज्ञापन

पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में सैकड़ों जगह स्वागत कार्यक्रम रखे गए, जिसमें पटेल वार्ड पार्षद त्रिवेंद्र जाट की तरफ से वार्डवासियों ने फूल माला, आतिशबाजी कर, फूल वर्षा करके भव्य स्वागत किया। पार्षद ने उमंग सिंघार को पटेल वार्ड देवरी की ढेर सारी समस्याओं को लेकर मौखिक रूप से अवगत कराकर व्यथा सुनाई एवं उनसे वार्ड विकास में हो रही समस्याओं एवं भेदभाव को लेकर सहयोग करने का निवेदन कर वार्ड की सभी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान सतीश राजोरिया, सुखदेव अरेले, राजू दीक्षित, ब्रजभान पटेल, पवन लोधी, रविंद्र लोधी, सचिन नामदेव, संतोष जाट, भीकम जाट, धर्मेंद्र साहू, बिट्टू सोनी आदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण एवं युवा कांग्रेस के लोग शामिल रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)